

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांक: 20 मई, 2011

विषय: अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना हेतु परिष्वय निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 763/मु0स0/स्पे0क0प्लान/2003-04, दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 645/04-11(एस.सी.पी./टी.एस.पी.)/2003, दिनांक 17 मार्च, 2004 के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (पूर्व में 'स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के नाम से सम्बोधित) एवं जनजाति उप योजना (ट्राईबल सब प्लान) के अन्तर्गत मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष वार्षिक/पंचवर्षीय योजना संरचना, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं तत्सम्बन्धी शोध-सर्वेक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नोडल विभाग घोषित करते हुए यह व्यवस्था की गयी थी कि नियोजन विभाग राज्य के कुल प्रस्तावित वार्षिक/पंचवर्षीय योजना आकार के आधार पर 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति उप योजना एवं 4 प्रतिशत जनजाति उप योजना हेतु एक मुश्त परिष्वय समाज कल्याण विभाग को आवंटित करेगा, जिसका नियोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों में यह उल्लिखित किया गया है कि अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना हेतु राज्य की वार्षिक/पंचवर्षीय योजना के परिष्वय में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समानुपातिक परिष्वय मात्राकृत किया जायेगा। राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का क्रमशः 17.9 प्रतिशत एवं 3.0 प्रतिशत होने के कारण अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना हेतु क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत परिष्वय का मात्राकरण सामान्यतः किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 एवं शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि नियोजन विभाग राज्य के कुल प्रस्तावित वार्षिक/पंचवर्षीय योजना आकार के आधार पर अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना हेतु क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत का एक मुश्त परिष्वय समाज कल्याण विभाग को आवंटित करेगा, जिसका नियोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों हेतु किया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 एवं शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2004 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,


(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या : 196 (1)/XVII(1)/11-99(प्रकोष्ठ)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(Signature)

(एम. एच. खान)
सचिव एवं आयुक्त।